

केंद्रीय बजट 2026-27:

एक आकलन

आकाश राज, हर्षिता यादव,
एट्टेम अभिग्न यादव, आयुषी खंडेलवाल,
अनूप के सुरेश, और श्रोमोना गांगुली द्वारा[^]

केंद्रीय बजट 2026-27 बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी आधारित विकास पर जोर देने के साथ विकास वृद्धि और राजकोषीय समेकन के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन बनाता है। यह उच्च पूंजीगत व्यय और स्वास्थ्य सेवा, एमएसएमई और हरित परिवर्तन में लक्षित क्षेत्रीय पहल के माध्यम से भारत के मध्यम अवधि के विकास दृष्टिकोण को मजबूत करता है। साथ ही, यह वृहद-आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए राजकोषीय घाटे में कमी का एक विश्वसनीय मार्ग बनाए रखता है। कुल मिलाकर, बजट भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन, नवाचार और समावेशी विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से एक दूरदर्शी रणनीति को दर्शाता है।

परिचय

केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत की आकांक्षा को मजबूत करते हुए राजकोषीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के समय में, बजट राजकोषीय समेकन के विश्वसनीय मार्ग को बनाए रखते हुए बुनियादी ढांचे के निवेश, तकनीकी आत्मनिर्भरता और मानव पूंजी विकास को प्राथमिकता देकर रणनीतिक दूरदर्शिता प्रदर्शित करता है। नवाचार, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और जलवायु के प्रति जागरूक विकास पर जोर एक लचीली और समावेशी भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। लक्षित क्षेत्रीय समर्थन के साथ वृहद आर्थिक स्थिरता को जोड़कर, यह बजट

[^] लेखक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च से हैं। मैनेजर देबप्रिया साहा और असिस्टेंट हर्षवर्धन हीरामन चौधरी की मदद के लिए शुक्रिया। लेखक इस आर्टिकल को तैयार करने में पूरी गाइडेंस के लिए श्रीमती संगीता दास के शुक्रगुजार हैं। इस आर्टिकल में बताए गए विचार लेखकों के हैं और ज़रूरी नहीं कि वे रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के विचारों से मेल खाते हों।

नीतिगत निरंतरता और सुधार के प्रति प्रतिबद्धता का एक मजबूत संकेत भेजता है।

प्राप्ति के मोर्चे पर, सकल कर राजस्व में 2026-27 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण आयकर संग्रह में त्वरित वृद्धि और 2025-26 (संशोधित अनुमान, आरई) में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की निरंतर वृद्धि है। व्यय पक्ष पर, पूंजीगत व्यय पर जोर जारी है। राजकोषीय समेकन के बावजूद, 2026-27 (बजट अनुमान, बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 3.1 प्रतिशत पर बनाए रखा जाएगा। प्रभावी पूंजीगत व्यय¹ 2025-26 (आरई) में जीडीपी के 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 2026-27 (बीई) में जीडीपी का 4.4 प्रतिशत हो जाएगा, जो विकास-बढ़ाने वाले खर्च पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। इसके साथ ही, राजस्व व्यय को 2025-26 (आरई) में जीडीपी के 10.8 प्रतिशत से 2026-27 (बीई) में जीडीपी के 10.5 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया है। राज्य सरकारों को अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (विधायिका के साथ) को ऋण के रूप में विशेष सहायता' को 2026-27 (बीई) में ₹2.0 लाख करोड़ के बढ़े हुए प्रावधान के साथ बढ़ाया गया है, जो 2025-26 (आरई) में ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को 2025-26 तक सकल राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के संबंध में की गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है। यह विकास को सुरक्षित करते हुए मजबूत सार्वजनिक वित्त को सक्षम करने के सरकार के दृष्टिकोण का प्रमाण है। 2026-27 के लिए, जीएफडी का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत है, जो 2030-31 तक 50 (+/-1) प्रतिशत के ऋण-से-जीडीपी अनुपात तक पहुंचने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। आगे बढ़ते हुए, ऋण-से-जीडीपी अनुपात का लक्षित मार्ग अन्य क्षेत्रीय व्यय के लिए संसाधनों को धीरे-धीरे मुक्त करने में मदद करेगा।

¹ इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और ग्रांट-इन-एड का कुल जोड़ है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, शेष लेख को आठ खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II में राजकोषीय घाटे के अंतर्निहित कारकों पर चर्चा की गई है, इसके बाद क्रमशः खंड III और IV में राजस्व और व्यय के रुझानों का विश्लेषण किया गया है। खंड V सरकार की बकाया ऋण स्थिति को रेखांकित करता है, जबकि खंड VI राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों पर केंद्रित है। खंड VII राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण की जांच करती है और खंड VIII अंतिम टिप्पणियों को प्रस्तुत करता है।

II. राजकोषीय घाटा - अंतर्निहित गतिशीलता

जैसा कि केंद्रीय बजट 2021-22 में परिकल्पना की गई है, केंद्र सरकार ने 2025-26 तक जीएफडी को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाकर अपने मध्यम अवधि के राजकोषीय समेकन पथ का पालन किया है। 2026-27 के लिए, जीएफडी का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत (2025-26 के लिए आरई में 4.4 प्रतिशत के मुकाबले) पर रखा गया है, जो 2030-31 तक 50 ± 1 प्रतिशत के ऋण-जीडीपी अनुपात के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। 2025-26 (आरई) की तुलना में 2026-27 में जीएफडी के बजटीय समेकन की परिकल्पना सकल घरेलू उत्पाद के 10.5 प्रतिशत [2025-26 (आरई) में 10.8 प्रतिशत] पर राजस्व व्यय को नियंत्रित करके की गई है, जबकि पूंजीगत व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 3.1 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। सकल कर राजस्व का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 11.2 प्रतिशत है, जो 2025-26 (आरई) में 11.4 प्रतिशत से मामूली कम है।

राजस्व व्यय से पूंजी परिव्यय (आरईसीओ) अनुपात - व्यय की गुणवत्ता का एक सारांश संकेतक - 2026-27 (बीई) में 4.4 पर स्थिर रहने का अनुमान है। 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2025-26 (आरई) में सकल घरेलू उत्पाद के 3.9 प्रतिशत से अधिक है [सारणी 1]।

जीएफडी का अपघटन

पूंजीगत परिव्यय 2026-27 (बीई) में जीएफडी के प्राथमिक घटक के रूप में बना हुआ है। हालांकि, जीएफडी में पूंजी परिव्यय

सारणी 1: मुख्य इंडिकेटर²

(जीडीपी का प्रतिशत)

वस्तु	2024-25	2025-26		2026-27
	वास्तविक	बीई	दोबारा	बीई
1	2	3	4	5
1. राजकोषीय घाटा	4.8	4.4	4.4	4.3
2. प्राथमिक घाटा	1.4	0.8	0.8	0.7
3. राजस्व घाटा	1.7	1.5	1.5	1.5
4. प्रभावी राजस्व घाटा	0.9	0.3	0.6	0.3
5. सकल कर राजस्व	11.5	12.0	11.4	11.2
6. गैर-कर राजस्व	1.6	1.6	1.9	1.7
7. राजस्व व्यय	10.9	11.0	10.8	10.5
8. पूंजीगत व्यय	3.2	3.1	3.1	3.1
जिसका कि:				
(i) पूंजीगत परिव्यय	2.6	2.5	2.5	2.4
9. प्रभावी पूंजीगत व्यय	4.0	4.3	3.9	4.4
10. ऋण	56.5	56.1	56.1	55.6

टिप्पणियाँ: 1. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए ग्रांट-इन-एड के बीच का अंतर है।

2. पूंजीगत परिव्यय, कैपिटल खर्च में से लोन और एडवांस घटाकर मिलने वाला हिस्सा है।

3. इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल खर्च और कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए ग्रांट-इन-एड मिलाकर मिलने वाला हिस्सा है।

4. एक्सटर्नल डेब्ट मौजूदा एक्सचेंज रेट पर लिया जाता है।

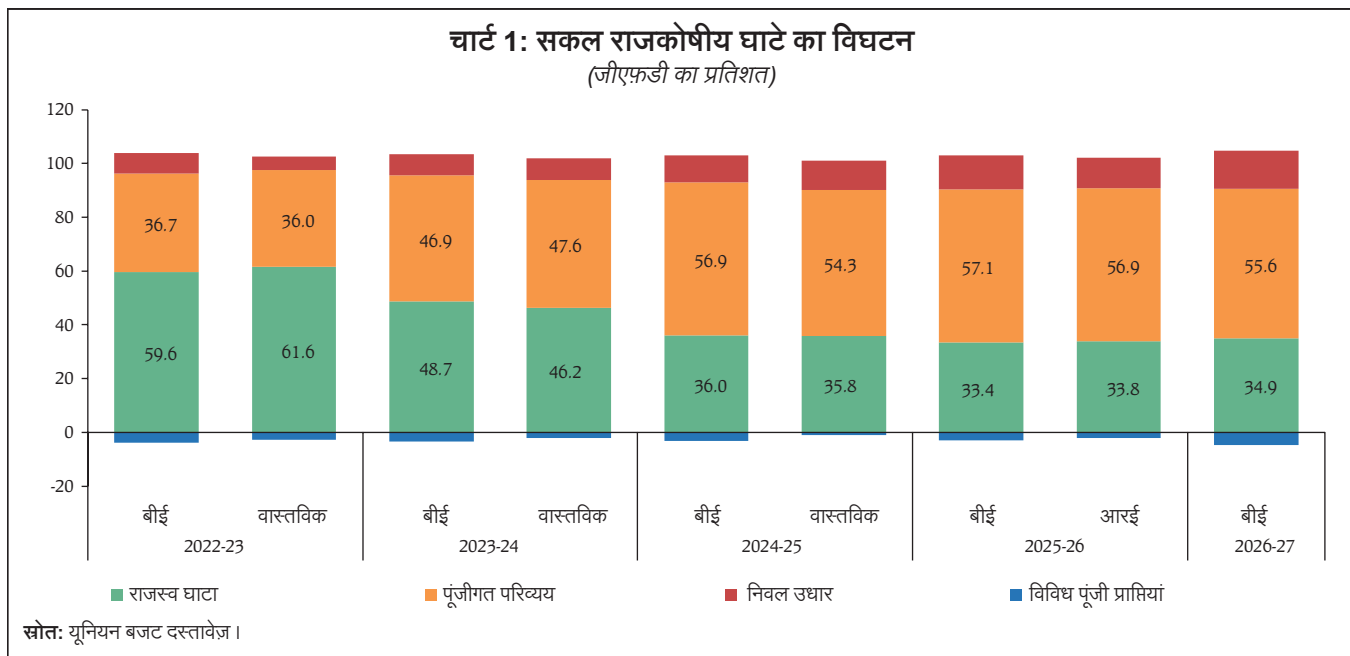
स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

का हिस्सा, जो 2019-20 से 2024-25 के दौरान औसतन 37.1 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 (आरई) में 56.9 प्रतिशत हो गया, 2026-27 में जीएफडी के 55.6 प्रतिशत तक मामूली रूप से गिरने का अनुमान है। राजस्व घाटे (आरडी) से पहले ही जीएफडी का हिस्सा, जो 2019-20 से 2024-25 के दौरान औसतन 60.0 प्रतिशत से घटकर 2025-26 (आरई) में 33.8 प्रतिशत हो गया था, 2026-27 में मामूली रूप से बढ़कर 34.9 प्रतिशत होने का अनुमान है (चार्ट 1)।

III. प्राप्ति

कुल गैर-ऋण प्राप्ति ने 2024-25 में 10.4 प्रतिशत की तुलना में 2025-26 (आरई) में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की [जीडीपी का 9.5 प्रतिशत के लिए लेखांकन] दर्ज की। 2025-26 के दौरान, सरकार की प्राप्ति को गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति और गैर-कर राजस्व में मजबूत वृद्धि द्वारा समर्थित किया गया था। 2026-27 (बजट अनुमान) के लिए, सरकार ने कुल गैर-ऋण प्राप्ति की वृद्धि में मामूली कमी का अनुमान लगाया है, जो मुख्य

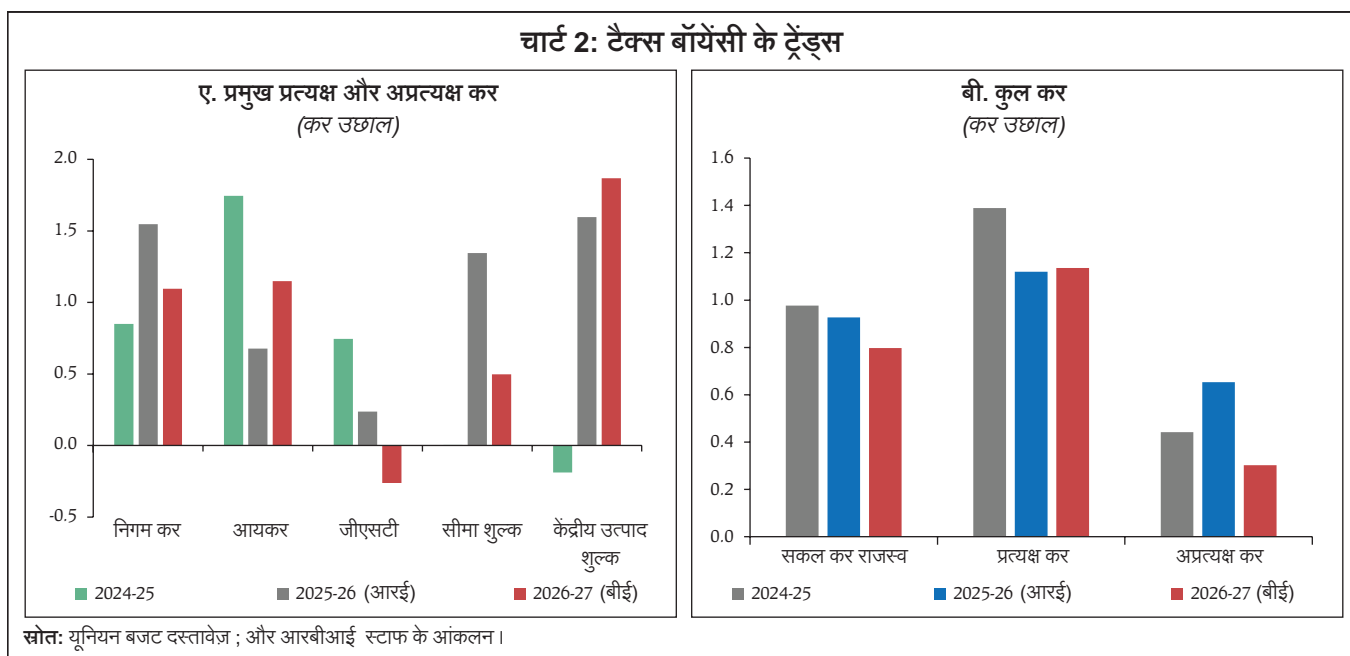
² विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक। देखें।

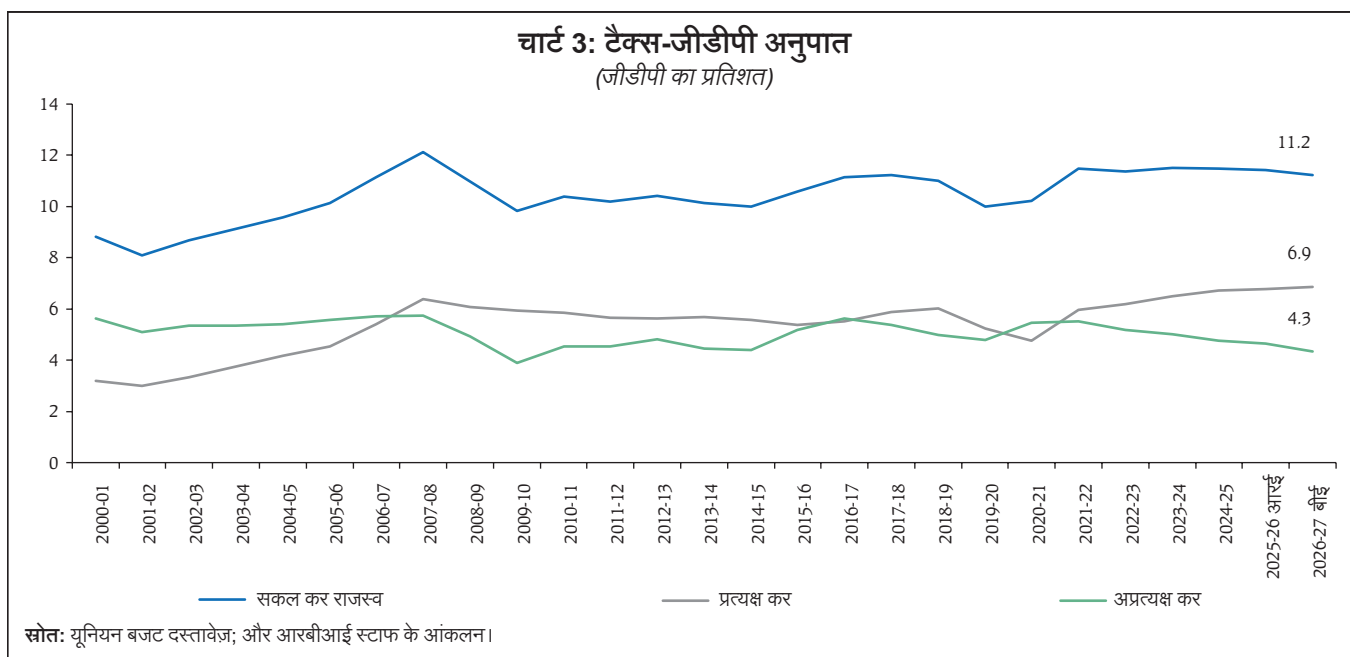


रूप से माल और सेवा कर (जीएसटी) से प्राप्तियों में संकुचन और गैर-कर राजस्व में मामूली गिरावट के लिए जिम्मेदार है। सकल कर राजस्व में 2026-27 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, साथ ही राज्यों को हस्तांतरण में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप 2026-27 (बजट अनुमान) के लिए शुद्ध कर राजस्व में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

कर राजस्व

आयकर और जीएसटी संग्रह में मंदी के कारण सकल कर राजस्व में 2024-25 की तुलना में 2025-26 (आरई) में 7.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, 2026-27 में इसमें 8.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। विशेष रूप से, प्रत्यक्ष कर 2025-26 (आरई) और 2026-27 (बीई) [चार्ट 2] में उत्साहजनक बने हुए हैं।





2026-27 में कर-जीडीपी अनुपात 11.2 प्रतिशत का बजट रखा गया है जो 2025-26 (आरई) में 11.4 प्रतिशत से मामूली रूप से कम है, जो मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष करों में नरमी के कारण है (चार्ट 3)। हालांकि, प्रत्यक्ष कर और जीडीपी अनुपात 2025-26 (आरई) में 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 2026-27 में 6.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।

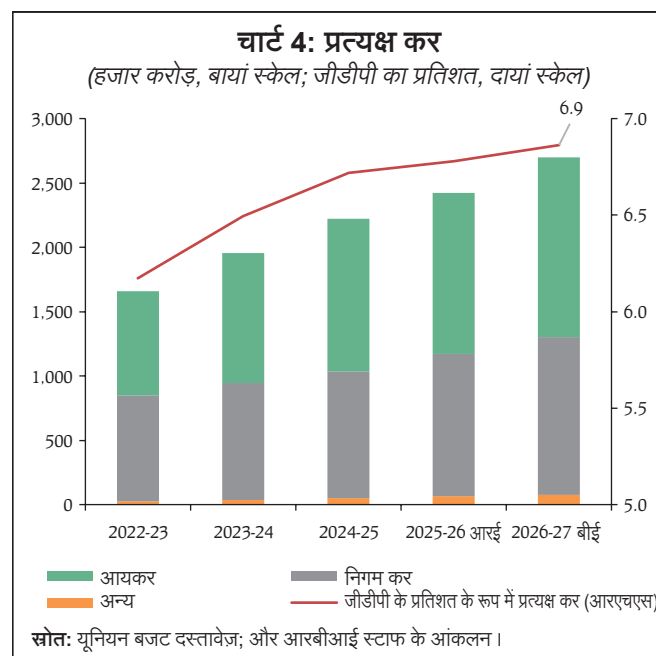
प्रत्यक्ष कर

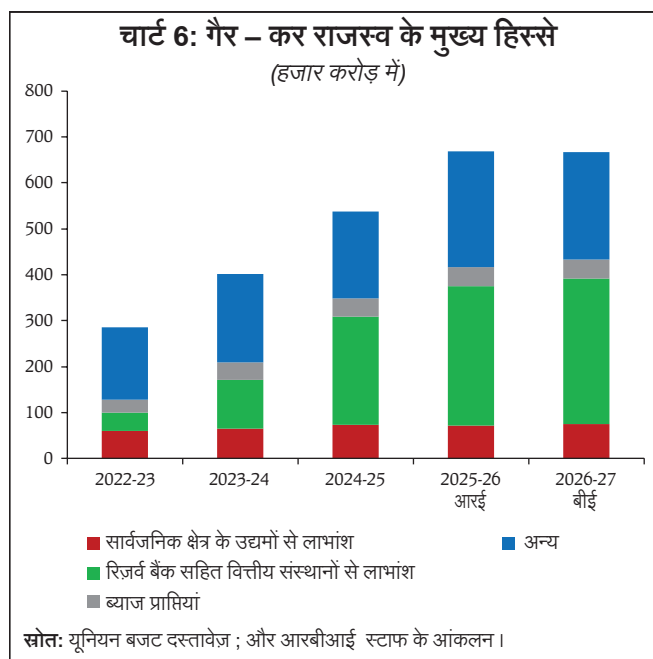
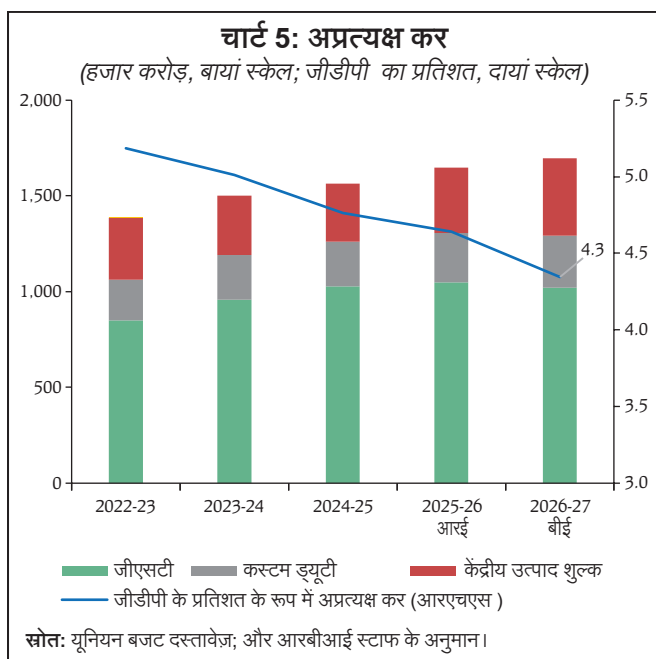
9.0 प्रतिशत की धीमी वृद्धि के साथ, 2025-26 (आरई) में प्रत्यक्ष कर 2025-26 के लिए बजटीय अनुमानों से नीचे रहा, मुख्य रूप से आयकर संग्रह में मंदी के कारण। हालांकि, निगम कर संग्रह बजटीय राशि से 27,000 करोड़ रुपये अधिक हो गया। 2026-27 के लिए, प्रत्यक्ष करों को उनकी विकास गति को बनाए रखने के लिए बजट बनाया गया है, जिसमें आयकर और निगम कर में क्रमशः 11.5 प्रतिशत और 11.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (चार्ट 4)।

अप्रत्यक्ष कर

2025-26 (संशोधित अनुमान) में अप्रत्यक्ष कर से प्राप्तियां (वर्ष-दर-वर्ष) 5.2 प्रतिशत बढ़ीं, लेकिन मुख्य रूप से जीएसटी संग्रह में मंदी के कारण बजटीय राशि से नीचे रहीं। विशेष रूप

से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से प्राप्तियां 2025-26 के लिए उनके संबंधित बजटीय अनुमानों से अधिक थीं। 2026-27 में, अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि का अनुमान 3.0 प्रतिशत तक मध्यम रहने का अनुमान है, जो जीएसटी संग्रह में संकुचन (जीएसटी दर युक्तिकरण के प्रभाव के लिए लेखांकन) और सीमा शुल्क में वृद्धि में गिरावट को दर्शाता है (चार्ट 5 और अनुलग्नक





1)। हालांकि, अनुपालन और दर संरचना के सरलीकरण के संदर्भ में जीएसटी ढांचे में सुधारों से आगे चलकर कर आधार का विस्तार होने की उम्मीद है।

गैर-कर राजस्व

2025-26 (आरई) में, गैर-कर राजस्व में 24.4 प्रतिशत की तेजी से वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से बजटीय अधिशेष/लाभांश हस्तांतरण से अधिक है। 2026-27 (बीई) के लिए, गैर-कर राजस्व (जीडीपी का 1.7 प्रतिशत के लिए लेखांकन) से संग्रह 2025-26 (आरई) [चार्ट 6] के संग्रह पर मामूली गिरावट दर्ज करने की उम्मीद है। हालांकि, इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश 2025-26 (आरई) में संकुचन दर्ज करने के बाद, 2026-27 में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति

उच्च वृद्धि (y-o-y) के बावजूद, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति 2025-26 (RE) में बजटीय अनुमानों से ₹11,974 करोड़ कम हो गई, जो विविध पूंजीगत प्राप्ति (विनिवेश आय सहित) में कमी के कारण थीं। 2026-27 में, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति को

विकास की गति को बनाए रखने के लिए बजट बनाया गया है, मुख्य रूप से ₹80,000 करोड़ के ऊंचे विविध पूंजीगत प्राप्ति के लक्ष्य के माध्यम से।³

IV. व्यय

2025-26 (आरई) के दौरान, केंद्र सरकार का कुल व्यय 7.4 प्रतिशत की बजटीय वृद्धि के मुकाबले 6.7 प्रतिशत बढ़ा। बहरहाल, यह 2024-25 में प्राप्त 4.7 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक रहा। 2025-26 (आरई) में कुल व्यय में इसकी बजटीय राशि से कम गिरावट राजस्व व्यय में ₹75,168 करोड़ के युक्तिकरण और आवंटित पूंजीगत व्यय के ₹25,335 करोड़ के कम उपयोग के कारण थी। 2026-27 के लिए, कुल व्यय का बजट 7.7 प्रतिशत की थोड़ी अधिक वृद्धि के लिए है, जिसमें राजस्व और पूंजीगत व्यय में क्रमशः 6.6 प्रतिशत और 11.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी (सारणी 2)। उच्च बजटीय पूंजीगत व्यय के अलावा, 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभाओं के

³ यूनियन बजट 2026-27 में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में मदद के लिए डेडिकेटेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) बनाने का प्रस्ताव है, जिससे वैल्यू अनलॉक होगी और सरकारी फाइनेंस को बढ़ावा मिलेगा।

सारणी 2: केंद्र सरकार का व्यय

वस्तु	₹ हजार करोड़				सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत				विकास दर (प्रतिशत)		
	2024-25	2025-26 (बीई)	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)	2024-25	2025-26 (बीई)	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)	2024-25	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. कुल व्यय	4,653	5,065	4,965	5,347	14.1	14.2	13.9	13.6	4.7	6.7	7.7
2. राजस्व व्यय (आरई)	3,601	3,944	3,869	4,125	10.9	11.0	10.8	10.5	3.1	7.4	6.6
(i) ब्याज भुगतान (आईपी)	1,116	1,276	1,274	1,404	3.4	3.6	3.6	3.6	4.9	14.2	10.2
(ii) कुल सब्सिडी (टीएस)	423	426	470	455	1.3	1.2	1.3	1.2	-2.8	11.1	-3.1
जिसका कि :											
खाना	200	203	228	228	0.6	0.6	0.6	0.6	-5.6	14.2	-0.2
उर्वरक	171	168	186	171	0.5	0.5	0.5	0.4	-9.4	9.2	-8.4
पेट्रोलियम	14	12	15	12	0.04	0.03	0.04	0.03	18.3	4.4	-20.1
(iii) आरई-आईपी-टीएस	2,063	2,242	2,125	2,267	6.2	6.3	6.0	5.8	3.4	3.0	6.7
(iv) पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ	274	277	287	296	0.8	0.8	0.8	0.8	14.9	4.7	3.3
(v) रक्षा (राजस्व)	291	312	350	365	0.9	0.9	1.0	0.9	0.2	20.2	4.5
3. पूंजीगत व्यय	1,052	1,121	1,096	1,222	3.2	3.1	3.1	3.1	10.8	4.2	11.5
(i) पूंजीगत परिव्यय	855	895	887	943	2.6	2.5	2.5	2.4	8.5	3.8	6.3
(ii) ऋण और अग्रिम	197	226	208	279	0.6	0.6	0.6	0.7	22.1	5.9	33.8

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़।

साथ) को ऋण के रूप में विशेष सहायता के तहत आवंटन को

पूंजी परिव्यय

2025-26 (आरई) में ₹1.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2026-27 (बजट अनुमान) में ₹2.0 लाख करोड़ कर दिया गया है, ताकि राज्य सरकारों को अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहित किया जा सके।

पूंजीगत परिव्यय की वृद्धि 2024-25 में 8.5 प्रतिशत से घटकर 2025-26 (आरई) में 3.8 प्रतिशत हो गई। बहरहाल, 2025-26 (आरई) की तुलना में 2026-27 में 6.3 प्रतिशत की उच्च वृद्धि का बजट रखा गया है [सारणी 3]। हाल के वर्षों में

सारणी 3: पूंजीगत परिव्यय

वस्तु	₹ हजार करोड़				विकास दर (प्रतिशत)		
	2024-25	2025-26 (बीई)	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)	2024-25	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कुल पूंजीगत व्यय	855	895	887	943	8.5	3.8	6.3
2. रक्षा सेवाएँ	160	180	218	229	3.6	36.5	5.1
3. पूंजीगत परिव्यय (डिफेंस को छोड़कर)	695	715	669	714	9.7	-3.8	6.7
(i) प्रमुख अवसंरचना (जिनमें से):	624	574	542	609	8.0	-13.2	12.4
क. परिवहन (जिसमें से):	545	513	512	561	6.0	-6.1	9.6
भारतीय रेल	252	252	252	278	3.9	0.02	10.3
सड़कें और पुल	292	259	259	282	8.1	-11.3	9.1
ख. संचार	75	50	24	46	23.5	-67.6	91.4
(ii) उद्योग और खनिज	13	12	11	10	102.1	-13.1	-8.7
(iii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	5	8	7	8	-23.8	26.2	21.8
(iv) अन्य	53	121	110	87	24.3	105.1	-21.0

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़।

पूंजीगत परिव्यय पर दिया गया जोर 2014-15 से 2019-20 के दौरान पंजीकृत 13.2 प्रतिशत की सीएजीआर की तुलना में 2020-21 से 2026-27 (बीई) के दौरान दर्ज 20.0 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में परिलक्षित होता है। प्रमुख बुनियादी ढांचा (परिवहन, संचार, ऊर्जा और सिंचाई) पूंजीगत परिव्यय का जोर बना रहा और 2020-21 से 2026-27 (बीई) के दौरान 29.3 प्रतिशत की सीएजीआर में दर्ज किया गया।

व्यय की गुणवत्ता

कोविड के बाद की अवधि में, केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करते हुए राजस्व व्यय को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। 2020-21 से 2026-27 (BE) के दौरान, राजस्व व्यय का सीएजीआर 2014-15 से 2019-20 के दौरान 9.9 प्रतिशत के सीएजीआर से घटकर 5.0 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) का अनुपात, जो सरकार के व्यय की गुणवत्ता का एक संकेतक है, हाल के वर्षों में लगातार गिर रहा है (चार्ट 7 ए)। इसी तरह, जीएफडी में राजस्व घाटे (आरडी) का हिस्सा हाल के वर्षों में घट रहा है (चार्ट 7बी)। सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता में यह सुधार जैसा कि आरईसीओ अनुपात और आरडी-जीएफडी अनुपात में

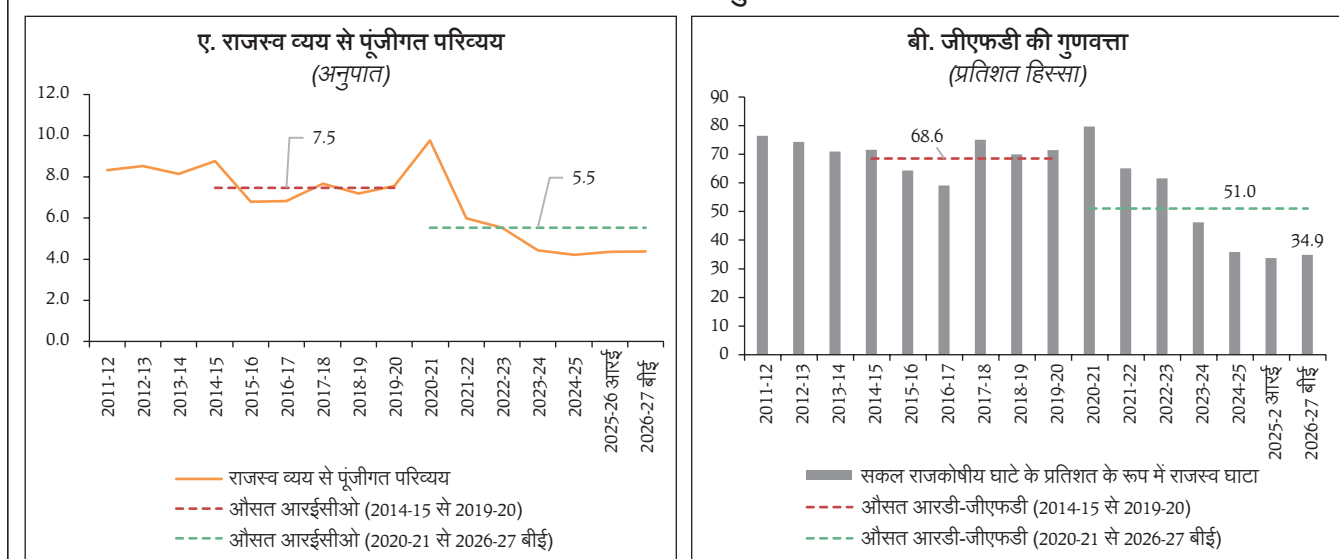
गिरावट की प्रवृत्ति में परिलक्षित होता है, राजकोषीय स्थिरता के लिए अच्छा संकेत है।

प्रमुख सरकारी योजनाएं

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर परिव्यय में 2025-26 (आरई) की तुलना में 2026-27 में क्रमशः 8.2 प्रतिशत और 30.6 प्रतिशत की वृद्धि करने का अनुमान है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में सबसे अधिक आवंटन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए किया गया है, इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का स्थान है। केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत गारंटी के लिए सर्वाधिक परिव्यय दिया गया है। विशेष रूप से, जल जीवन मिशन के लिए आवंटन में पिछले दो वर्षों में संकुचन के बाद 2026-27 (बीई) में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है (सारणी 4)।

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों पर परिव्यय राज्यों को अंतरित संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा होता है। इन योजनाओं के तहत राज्यों को धन प्रवाह में दृश्यता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने 2021 में एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) ढांचे को लागू किया था। इसमें व्यय की गति के आधार पर राज्यों

चार्ट 7: खर्च की गुणवत्ता



⁴ गिरते आरईसीओ अनुपात का मतलब है कि सरकार के खर्च की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

सारणी 4: प्रमुख सरकारी योजनाओं पर व्यय

वस्तु	₹ हजार करोड़				कुल व्यय का प्रतिशत			विकास दर (प्रतिशत)		
	2024-25	2025-26 (बीई)	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)	2024-25	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)	2024-25	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ए. केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (जिनमें से) :	1,494	1,622	1,637	1,772	32.1	33.0	33.1	5.0	9.6	8.2
1. पीएम-किसान	66	64	64	64	1.4	1.3	1.2	7.6	-4.0	0.0
2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई)	200	203	228	227	4.3	4.6	4.3	-	14.2	-0.1
3. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)	23	23	23	23	0.5	0.5	0.4	58.6	0.0	0.0
4. पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना	8	20	17	22	0.2	0.3	0.4	-	117.5	29.4
5. फसल बीमा योजना	14	12	12	12	0.3	0.2	0.2	11.8	-15.2	-0.5
बी. केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (जिनमें से):	402	542	420	549	8.6	8.5	10.3	-9.5	4.4	30.6
1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा)	86	86	88	30	1.8	1.8	0.6	-3.7	2.5	-65.9
2. विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी [बीबी-जी रैम योजना]	-	-	-	96	-	-	1.8	-	-	-
3. जल जीवन मिशन (जेजेएम) / राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	23	67	17	68	0.5	0.3	1.3	-67.7	-24.8	298.1
4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी)	38	78	40	77	0.8	0.8	1.4	-12.1	5.5	89.9
5. समग्र शिक्षा	36	41	38	42	0.8	0.8	0.8	10.5	4.7	10.8
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम*	32	30	30	32	0.7	0.6	0.6	27.5	-5.7	6.5
7. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (अम्ब्रेला आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना)	21	22	21	23	0.5	0.4	0.4	-3.6	-0.3	10.3

-: उपलब्ध नहीं है।
*: रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ (आरसीएच) और हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए फ्लेक्सिबल पूल, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन से संबंधित है।
टिप्पणी: बीबी-जी आरएएम जी स्कीम मानरेगा की जगह लेगी, लेकिन 2026-27 के लिए दोनों स्कीमों के लिए अलॉटमेंट कर दिया गया है। सोर्स: यूनियन बजट दस्तावेज।

को योजना निधियों को समय पर जारी करना सुनिश्चित करना और निधियों की फ्लोट/निष्क्रिय पार्किंग से बचना है जो ब्याज

लागत की बचत और पारदर्शी बजट (बॉक्स ए) की सुविधा प्रदान करता है।

बॉक्स A: ट्रेजरी एकल खाता और सेंटर द्वारा नकदी प्रबंधन

व्यय प्रबंधन आयोग (2015) की सिफारिशों के बाद, केंद्र से अनुदान प्राप्त करने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए, पायलट आधार पर भारत में 2017-18 के दौरान ट्रेजरी एकल खाता (टीएसए) को पहली बार अपनाया गया था। इसके बाद, 2021 में, सरकार ने केंद्र प्रायोजित

योजनाओं⁵ के लिए सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) मॉडल लागू किया। 2022 में, टीएसए ढांचे को ₹500 करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं तक बढ़ा दिया गया, और जून 2024 में इस सीमा को संशोधित कर ₹100 करोड़⁶ कर दिया गया। इन सुधारों का उद्देश्य सरकार की उधार लेने की लागत को कम करना और लाभार्थियों/

(जारी)

⁵ केंद्रीय रूप से प्रायोजित वे स्कीम होती हैं जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वित्त पोषित करती हैं और राज्य सरकारें ही लागू करती हैं। एसएनए फ्रेमवर्क के तहत, हर स्टेट को हर केंद्रीय रूप से प्रायोजित के लिए एक एसएनए डेज़िग्नेट करना होता है, और स्टेट लेवल पर एक कमर्शियल बैंक में एक नोडल अकाउंट खोला जाता है। सेंटर से फंड रिज़र्व बैंक के ज़रिए इन अकाउंट में आते हैं, जबकि स्टेट का हिस्सा सीधे स्टेट के ट्रेजरी से इन अकाउंट में रिलीज़ किया जाता है।
⁶ सेंट्रल सेक्टर स्कीम वे स्कीम हैं जिन्हें पूरी तरह से केंद्र सरकार फंड करती है और जिन्हें केंद्र सरकार की मशीनरी लागू करती है। हर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए, संबंधित विभाग/मंत्रालय एक ऑटोनॉमस बॉडी या सेंट्रल नोडल एजेंसी (सीएनए) और उसकी उप-एजेंसी (एसएएस) बनाती है; सीएनए रिज़र्व बैंक के साथ ई-कुबेर में अकाउंट खोलती हैं। एसएनए/सीएनए फ्रेमवर्क के तहत आने वाली स्कीम के लिए, सभी रसीदें और पेमेंट सेंट्रलाइज़्ड अकाउंट के ज़रिए किए जाते हैं, जिससे अलग-अलग लेवल पर कई अकाउंट का पिछला सिस्टम खत्म हो जाता है।

विक्रेताओं को संबंधित मंत्रालय/विभाग से धन की 'जस्ट-इन टाइम' रिलीज' की ओर बढ़कर और धन के फ्लोट/निष्क्रिय पार्किंग से बचकर फंड प्रवाह में दक्षता बढ़ाना था।

⁸का उपयोग करके केंद्र सरकार के नकदी प्रबंधन अभ्यास पर एसएनए को अपनाने के प्रभाव का आकलन करने की दिशा में एक प्रयास किया गया है। ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी (एआरसीएच) मॉडल का उपयोग नमूना अवधि अप्रैल 1997 से दिसंबर 2025 के लिए नकदी संतुलन अस्थिरता पर एसएनए के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। नकदी शेष (बाजार उधार के शुद्ध)⁹ की गणना नकदी प्रवाह और बहिर्वाह के बीच के अंतर के रूप में की जाती है, जिसमें गैर-ऋण प्राप्तियां और गैर-बाजार उधार एक साथ नकदी प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं और कुल व्यय नकदी बहिर्वाह¹⁰ होता है (चंदर, 2014)। नकदी शेष पर एसएनए के प्रभाव का आकलन करने के लिए, जुलाई 2021 के लिए एक डमी चर जोड़ा गया है

प्रतिगमन के परिणामों से संकेत मिलता है कि एसएनए को अपनाने से नकदी शेष की अस्थिरता पर सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जो नकदी प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार का सुझाव देता है। इसके अलावा, यह पाया गया कि गैर-ऋण प्राप्तियों और कुल व्यय का सशर्त विचरण पर सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गैर-ऋण प्राप्तियों में वृद्धि के साथ नकदी शेष की अस्थिरता कम हो जाती है, और व्यय में वृद्धि के साथ यह बढ़ जाती है। एआरसीएच शब्द का प्रतिगमन गुणांक सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण है जो यह सुझाव देता है कि नकदी शेष में अस्थिरता पिछले झटकों से प्रेरित है और अस्थिरता क्लस्टरिंग को प्रदर्शित करता है (सारणी A.1)।

हाल के वर्षों में, जिन दिनों के लिए केंद्र ने अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाओं का सहारा लिया है, उनकी संख्या में गिरावट आई है, जो केंद्र द्वारा अपनाए गए बेहतर नकदी प्रबंधन प्रथाओं का संकेत है (चार्ट ए.1)।

सारणी A.1: रिग्रेशन परिणाम (डिपेंडेंट वेरिएबल: नेट कैश बैलेंस)	
स्वतंत्र प्रभावित करने वाली वस्तुएँ	प्रतिगमन गुणांक
माध्य समीकरण	
स्थिर	-10.943* (2.166)
एआरएमए संरचना	
एमए(1)	0.204* (0.029)
एमए(12)	0.542* (0.039)
सशर्त विचरण	
आर्क(2)	0.449* (0.093)
गुणक विषमस्केडैस्टिसिटी	
स्थिर	4.545* (0.191)
एसएनए अपनाने के लिए डमी	-1.821* (0.473)
गैर-ऋण प्राप्तियां	-0.004* (0.001)
कुल व्यय	0.020* (0.002)
सारांश	
अवलोकनों की संख्या	345
लॉग संभावना	-1715.79

टिप्पणी: 1. ब्रैकेट में दिए गए आंकड़े स्टैंडर्ड एरर हैं।

2. * 5 परसेंट पर सिग्निफिकेंस लेवल दिखाता है।

टीएसए और एसएनए की सफलता के आधार पर, केंद्र ने वर्तमान में कई चरणों में कार्यान्वयन को बढ़ाया है जैसे: (ए) 'एसएन-सेंट्रल' मॉड्यूल एसएनए को पहले से बाहर की गई केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं तक विस्तारित करता है (अप्रैल 2023 से); (ख) निजी उप-एजेंसियों को शामिल करते हुए केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए टीएसए हाइब्रिड, जो जून, 2024 से लागू है; और (सी) एसएनए स्पर्श (समग्र रूप से क्षेत्रों में भुगतान और रिपोर्टिंग के लिए प्रणाली) जिसे शुरू में 2023 में पायलट आधार पर छह राज्यों (राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़) में दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं (पीएम उषा और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण) के लिए शुरू किया गया था और बाद में योजनाओं के एक व्यापक सेट तक विस्तारित किया गया था¹¹

(समाप्त)

⁷ फंड का जस्ट-इन-टाइम रिलीज यह पक्का करता है कि फंड तभी रिलीज किया जाए जब खर्च के लिए उसकी ज़रूरत हो, एडवांस में नहीं। इससे किसी भी लेवल पर फंड पार्क करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है, कैश का इस्तेमाल बेहतर होता है और उन एजेंसियों का फाइनेंशियल अनुशासन बेहतर होता है जिनके ज़रिए सरकारी स्कीमें लागू की जाती हैं।

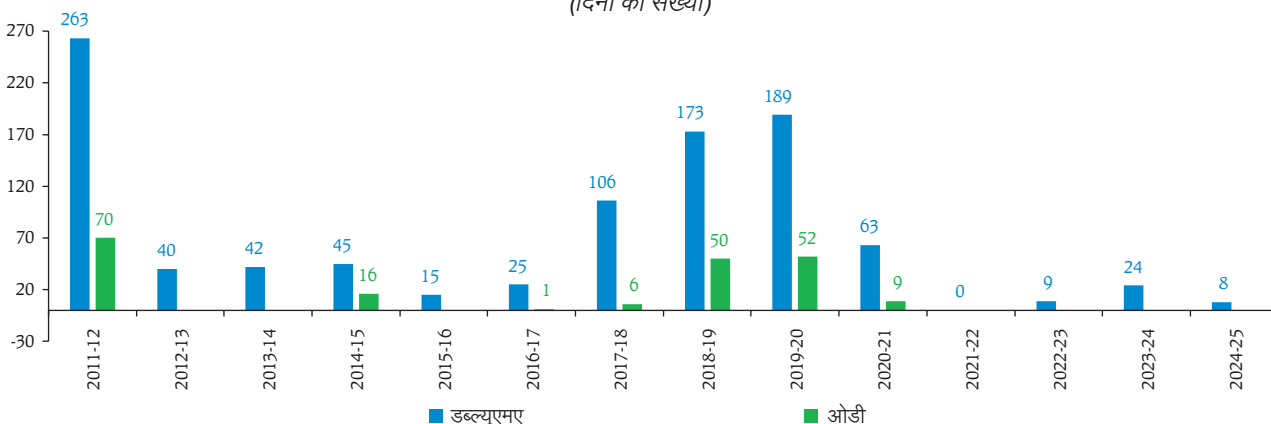
⁸ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा जारी किए गए मंथली डेटा का इस्तेमाल करके सेंटर के कैश बैलेंस के फ्लो कंपोनेंट का एनालिसिस किया गया है।

⁹ चंदर (2014) के तरीके के हिसाब से, मार्केट से उधार लेने को एनालिसिस से बाहर रखा गया है, क्योंकि सरकार कैश बैलेंस में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है।

¹⁰ नॉन-डेट रिसीट में रेवेन्यू रिसीट और नॉन-डेट कैपिटल रिसीट शामिल हैं। नॉन-मार्केट उधार में पब्लिक अकाउंट (जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड (एनएसएसएफ), स्पेशल डिपॉजिट, स्टेट प्रोविडेंट फंड वगैरह) से रिसीट और बाहरी उधार शामिल हैं।

¹¹ यूनियन बजट डॉक्यूमेंट 2026-27 के अनुसार, 81 नोटिफाइड केंद्रीय रूप से प्रायोजित में से 50 को 31 दिसंबर, 2025 तक एसएनए-स्पर्श में शामिल कर लिया गया है।

चार्ट ए.1: केंद्र सरकार द्वारा डबल्यूएमए/ओडी सुविधा का उपयोग
(दिनों की संख्या)



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक, वार्षिक रिपोर्ट (विभिन्न वर्ष)।

टीएसए और एसएनए प्रणालियों को विभिन्न मंत्रालयों से मासिक/त्रैमासिक नकदी प्रवाह पूर्वानुमान, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के हिस्से के रूप में स्वचालित दैनिक नकद शेष रिपोर्ट और ऑफ-बजट उधार (पंद्रहवां और सोलहवां वित्त आयोग) में कमी पर जोर देने से पूरक किया जाता है। बड़ी संख्या में योजनाओं पर एसएनए-स्पर्श का चल रहा विस्तार एक पारदर्शी और कुशल नकदी प्रबंधन

प्रणाली स्थापित करने की दिशा में सरकार के प्रयास को और मजबूत करेगा।

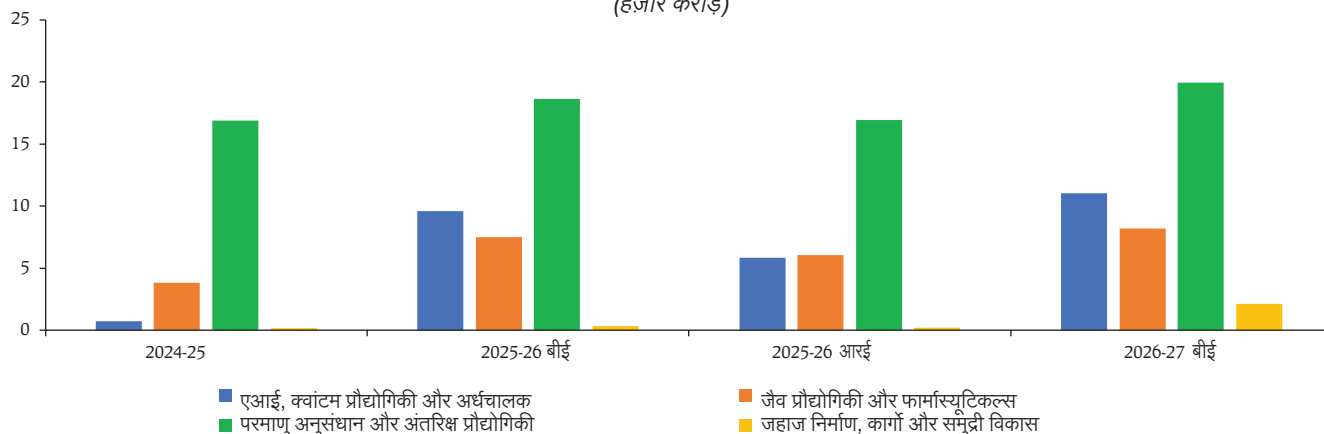
References:

Chander, J. (2014). Government Cash Operations: Volatility and Management in India. Reserve Bank of India Occasional Papers, Vol. 35 and 36, No 1 and 2: 2014 & 2015.

हाल के वर्षों में, केंद्र सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और जहाज निर्माण जैसे नए उभरते रणनीतिक क्षेत्रों के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), परमाणु अनुसंधान

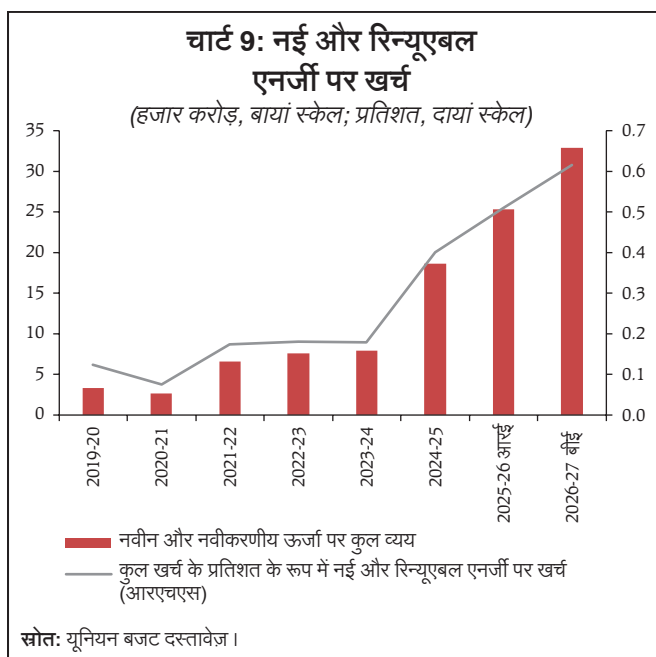
और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (चार्ट 8) जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर केंद्रित क्षेत्रों के लिए समर्पित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के आवंटन में भी वृद्धि की है।

चार्ट 8: उभरते रणनीतिक क्षेत्रों पर व्यय
(हज़ार करोड़)



टिप्पणी: एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और सेमी-कंडक्टर में शामिल स्कीम हैं भारत-विस्तार, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए मॉडिफाइड प्रोग्राम, इंडियाआई मिशन, और नेशनल क्वांटम मिशन। शिपबिल्डिंग कार्गो, और मैरीटाइम डेवलपमेंट के लिए 'शिप बिल्डिंग में मदद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (एसबीएफएस) और नेशनल शिपबिल्डिंग मिशन, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए स्कीम, और भारत में शिपबिल्डिंग के लिए क्रेडिट रिस्क कवरेज- शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम (एसबीडीएस)। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, और कार्गो प्रमोशन स्कीम – जलवाहक शामिल हैं।

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़।

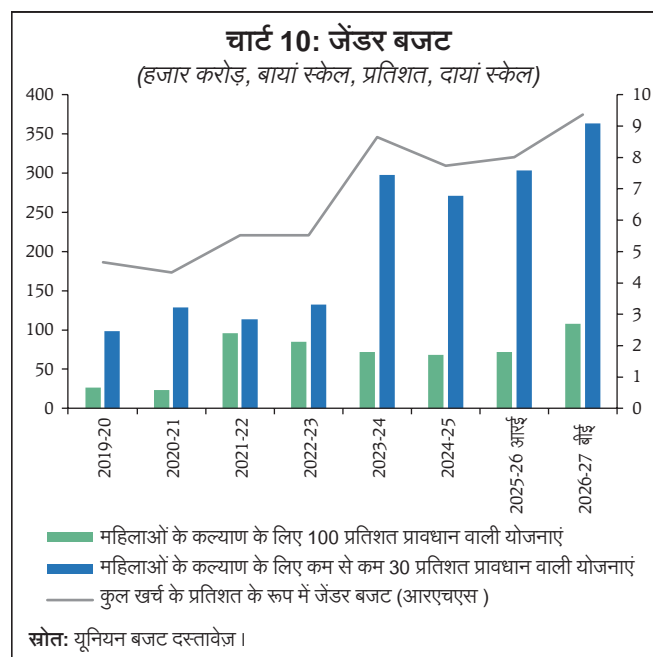


नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए व्यय को 2026-27 में कुल व्यय का 0.6 प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुमान है, जिसके कारण पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (चार्ट 9) के लिए आवंटन में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए कुल आवंटन का 93.2 प्रतिशत सौर ऊर्जा है। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का जेंडर बजट 2025-26 (आरई) में 8.0 प्रतिशत की तुलना में 2026-27 में 9.4 प्रतिशत पर बजटीय है।

V. बकाया ऋण

कोविड-19 महामारी के बीच 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 62.6 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद, केंद्र सरकार के कुल बकाया ऋण में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राजकोषीय एंकर¹² के रूप में ऋण-से-जीडीपी अनुपात को जारी रखते हुए, केंद्र सरकार ने मार्च 2031 तक ऋण-से-जीडीपी अनुपात को 50 (+/-1) प्रतिशत तक लाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्र सरकार का ऋण-से-जीडीपी अनुपात 2026-27 में सकल घरेलू उत्पाद के 55.6 प्रतिशत तक समेकित होने का अनुमान है, जो 2025-26 (आरई) में जीडीपी के 56.1 प्रतिशत से कम है। राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान अनुपात

¹² यूनियन बजट 2025-26 में, सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2030-31 तक के लिए डेट-टू-जीडीपी रेश्यो को फिस्कल एंकर के तौर पर घोषित किया था।



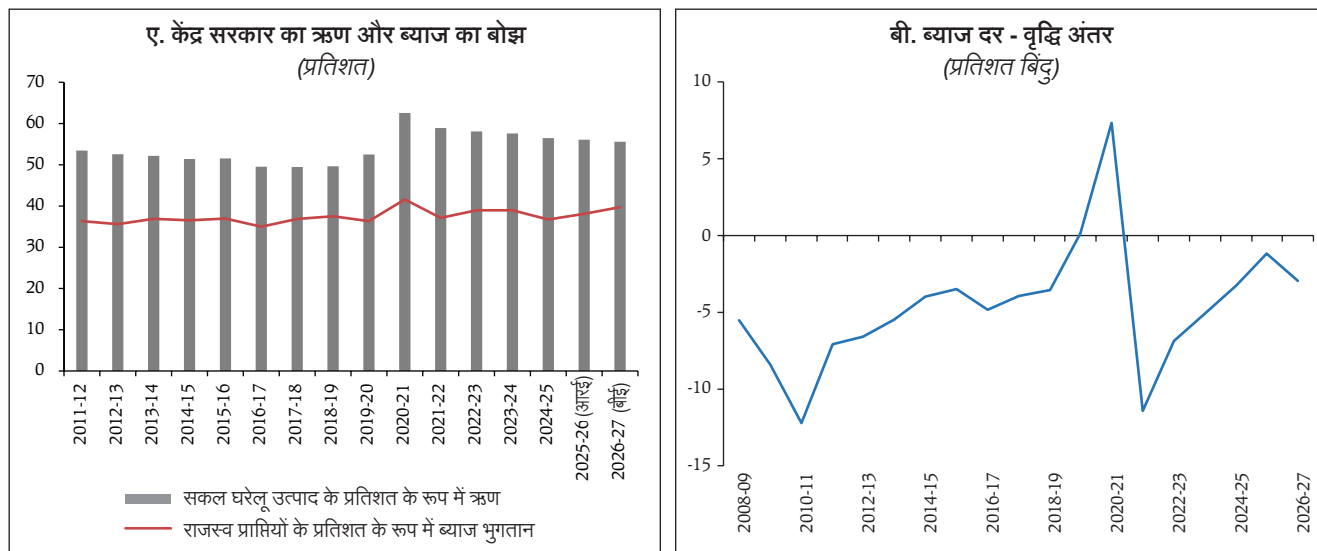
2025-26 (आरई) में 38.1 प्रतिशत की तुलना में 2026-27 में 39.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ब्याज दर-वृद्धि अंतर (आईआरजीडी), ऋण स्थिरता का एक संकेतक, अनुकूल रहता है (चार्ट 11 ए और बी)।

VI. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

वित्तपोषण पक्ष पर, 2026-27 के लिए सकल और शुद्ध बाजार उधारी का बजट क्रमशः 17.2 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 4.4 प्रतिशत) और 11.7 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.0 प्रतिशत) है। 2025-26 (आरई) में जीएफडी के 72.7 प्रतिशत की तुलना में 2026-27 (बीई) में शुद्ध बाजार उधारी से जीएफडी का 69.2 प्रतिशत वित्त पोषण होने का अनुमान है। जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार, 2026-27 में शुद्ध बाजार उधारी में गिरावट का अनुमान है। लघु बचत और शुद्ध ट्रेजरी बिलों के खिलाफ जारी की गई प्रतिभूतियों के लिए क्रमशः ₹3.9 लाख करोड़ और ₹1.3 लाख करोड़ की राशि है, जो 2026-27 में जीएफडी के क्रमशः 22.8 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत को वित्त पोषित करने के लिए बजटीय हैं (चार्ट 12)।

महामारी से पहले के स्तर की ओर केंद्र सरकार की शुद्ध बाजार उधार आवश्यकताओं (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार) में धीरे-धीरे कमी से निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों

चार्ट 11: बकाया देनदारियां और ब्याज दर-विकास अंतर



स्रोत: यूनिथन बजट दस्तावेज़; और आरबीआई स्टाफ के आंकलन।

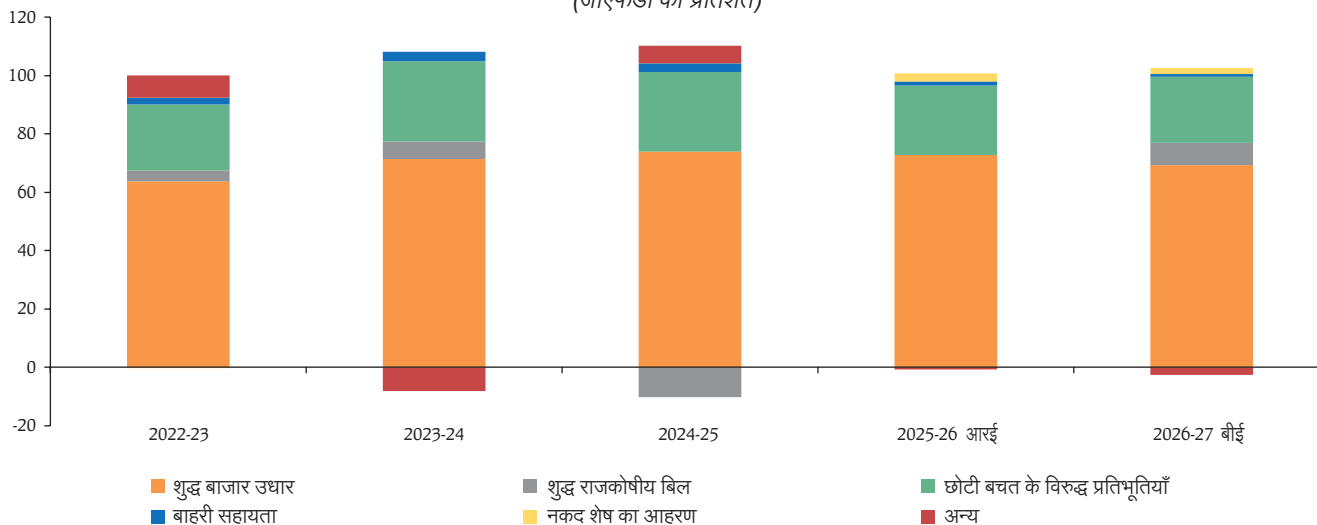
की अधिक उपलब्धता की सुविधा मिलने की उम्मीद है (तालिका 5)।

VII. केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण

राज्यों को सकल हस्तांतरण को 2025-26 (आरई) के दौरान 5.0 प्रतिशत से 2026-27 (बजट अनुमान) में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि करने का बजट रखा गया है, जो मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हस्तांतरण और पूंजी निवेश के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (विधायिका के साथ) को ऋण

के रूप में विशेष सहायता के कारण है। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में राज्यों को संसाधनों का सकल हस्तांतरण 2025-26 (आरई) के दौरान 6.5 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 2026-27 (बजट अनुमान) के दौरान 6.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2026-27 के लिए, बजट में राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2025-26 (आरई) की तुलना में 33.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। करों में राज्यों की

चार्ट 12: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत (जीएफडी का प्रतिशत)



स्रोत: यूनिथन बजट दस्तावेज़।

सारणी 5: केंद्र सरकार का बाज़ार उधार

(₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष	सकल बाज़ार उधार	शुद्ध बाज़ार उधार
1	2	3
2019-20	7,10,000 (3.5)	4,73,968 (2.4)
2020-21	12,60,116 (6.3)	10,32,907 (5.2)
2021-22	9,68,382 (4.1)	7,04,097 (3.0)
2022-23	14,21,000 (5.3)	11,08,259 (4.1)
2023-24	15,43,000 (5.1)	11,80,458 (3.9)
2024-25	14,00,697 (4.2)	11,62,878 (3.5)
2025-26 (आरई)	14,61,000 (4.1)	11,32,834 (3.2)
2026-27 (बीई)	17,20,000 (4.4)	11,73,210 (3.0)

टिप्पणियाँ: 1. ग्राँस मार्केट बॉरोइंग में सिर्फ़ नए बॉरोइंग शामिल हैं।
2. नेट मार्केट बॉरोइंग में बायबैक और सिक्योरिटीज़ की स्विचिंग का असर शामिल नहीं है।
3. ब्रैकेट में दिए गए आंकड़े जीडीपी के परसेंट के हिसाब से हैं।

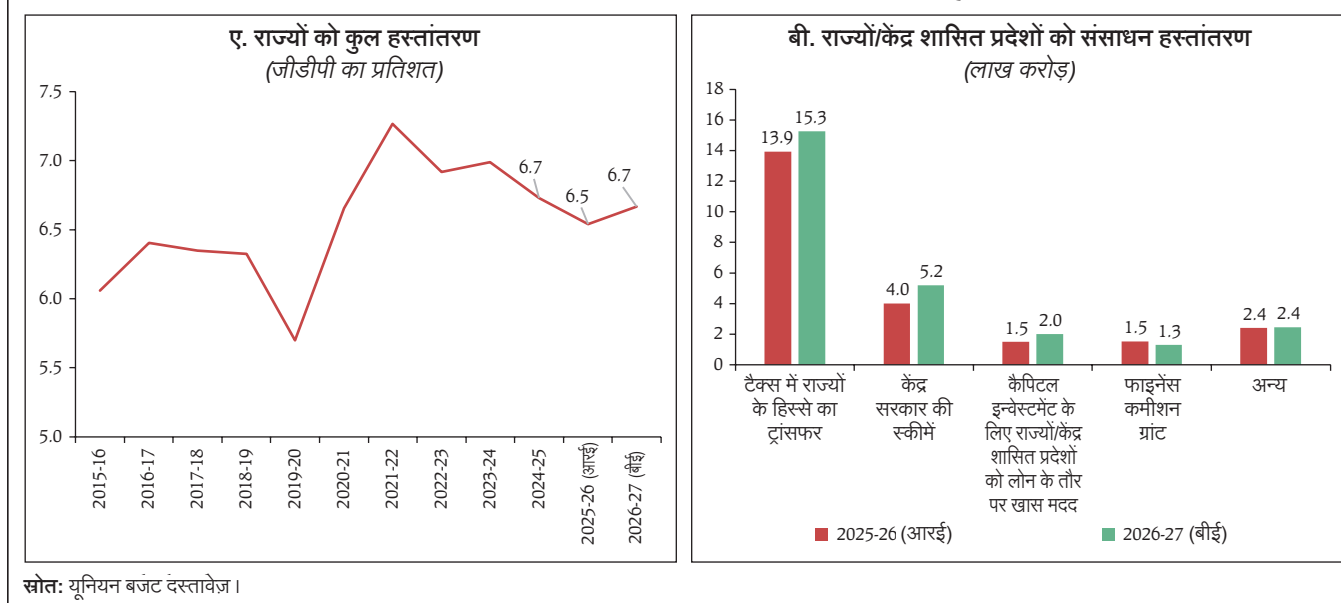
स्रोत: यूनिशन बजट दस्तावेज़।

हिस्सेदारी का अंतरण सकल हस्तांतरण का सबसे बड़ा घटक है (चार्ट 13)।¹³

वित्त आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले¹⁴ अनुदानों में 2026-27 में 15.4 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। इसके भीतर, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान में वृद्धि जारी है, शहरी स्थानीय निकायों के लिए उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि आपदा प्रबंधन अनुदान में गिरावट देखी गई है। अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दिया गया है (तालिका 6)।

केंद्र ने राज्यों में क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक क्षमता और सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की घोषणा की है। यह खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और स्थायी चुम्बकों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारों की स्थापना में खनिज समृद्ध राज्यों का समर्थन करेगा। घरेलू रासायनिक उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए राज्यों को तीन प्लग-एंड-प्ले केमिकल पार्क स्थापित करने में मदद करने के लिए एक चुनौती-आधारित योजना शुरू की जाएगी। केंद्र चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने और डॉक्टरों और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों के निर्माण का भी समर्थन करेगा। इसके अलावा, शिक्षा, अनुसंधान, कौशल और आवास

चार्ट 13: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सकल संसाधन हस्तांतरण



¹³ विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक II देखें।

¹⁴ वित्त आयोग की सिफारिशों के विवरण के लिए, कृपया अनुलग्नक III देखें।

सारणी 6: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फाइनेंस कमीशन (एफसी) ग्रांट

वस्तु	₹ लाख करोड़		कुल एफसी अनुदानों में हिस्सा (प्रतिशत में)		वृद्धि (प्रतिशत)	
	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)
वित्त आयोग (एफसी) अनुदान	1.5	1.3	-	-	26.6	-15.4
1. स्थानीय निकायों – शहरी निकायों के लिए अनुदान	0.3	0.5	17.0	35.0	35.1	74.0
2. स्थानीय निकायों – ग्रामीण निकायों के लिए अनुदान	0.5	0.6	35.5	43.2	31.6	2.9
3. आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान	0.3	0.3	21.9	21.8	32.7	-15.8
4. हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान	0.1	-	9.0	-	-44.0	-
5. अन्य*	0.3	-	16.6	-	139.5	-

*: इसमें हेल्थ सेक्टर के लिए ग्रांट और शेयर्ड म्युनिसिपल सर्विसेज के लिए ग्रांट शामिल हैं।

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़।

को एकीकृत करने के लिए प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स गलियारों के पास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। केंद्र प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नारियल संवर्धन योजना शुरू करेगा। पूर्वोदय पहल के तहत, यह एक एकीकृत ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करेगा, नए पर्यटन स्थलों का निर्माण करेगा और ई-बसें प्रदान करेगा। इसने विरासत स्थलों को संरक्षित करके, कनेक्टिविटी में सुधार करके और तीर्थ सुविधाओं को उन्नत करके चुनिंदा उत्तर-पूर्वी राज्यों में बौद्ध सर्किट विकसित करने की एक योजना की भी घोषणा की है।

VIII. निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2026-27 में समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा को संतुलित करते हुए विकसित भारत की दिशा में एक मार्ग की परिकल्पना की गई है। जबकि सरकार ने पूंजीगत व्यय पर अपना जोर जारी रखा, इसने 2025-26 (आरई) में सकल राजकोषीय घाटे के 4.4 प्रतिशत के सकल राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करके और 2026-27 (बजट अनुमान) में इसे और कम करके 4.3 प्रतिशत तक राजकोषीय समेकन के अपने वादे को भी पूरा किया।

अनुलग्नक I: केंद्रीय बजट 2026-27: मुख्य वित्तीय संकेतक

वस्तु	₹ हजार करोड़					सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत			विकास दर		
	2023-24	2024-25	2025-26 (बीई)	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)	2024-25	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)	2024-25	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. प्रत्यक्ष कर	1,956	2,222	2,520	2,421	2,697	6.7	6.8	6.9	13.6	9.0	11.4
(i) निगम कर	911	987	1,082	1,109	1,231	3.0	3.1	3.1	8.3	12.4	11.0
(ii) आयकर	1,011	1,184	1,360	1,248	1,392	3.6	3.5	3.5	17.1	5.4	11.5
(iii) सुरक्षा लेनदेन कर	34	52	78	64	74	0.2	0.2	0.2	54.5	22.0	15.8
2. अप्रत्यक्ष कर	1,509	1,574	1,750	1,657	1,707	4.8	4.6	4.3	4.3	5.2	3.0
(i) जीएसटी	957	1,027	1,178	1,046	1,019	3.1	2.9	2.6	7.3	1.9	-2.6
(ii) सीमा शुल्क	233	233	240	258	271	0.7	0.7	0.7	0.04	10.8	5.0
(iii) उत्पाद शुल्क	309	304	322	342	407	0.9	1.0	1.0	-1.8	12.8	18.8
3. सकल कर राजस्व (1+2)	3,466	3,796	4,270	4,078	4,404	11.5	11.4	11.2	9.5	7.4	8.0
4. राज्यों को असाइनमेंट	1,129	1,287	1,422	1,393	1,526	3.9	3.9	3.9	13.9	8.2	9.6
5. एनसीसीडी ट्रांसफर	9	9	10	10	11	0.03	0.03	0.03	7.8	7.2	7.6
6. शुद्ध कर राजस्व (3-4-5)	2,327	2,500	2,837	2,675	2,867	7.6	7.5	7.3	7.4	7.0	7.2
7. गैर-कर राजस्व	402	537	583	668	666	1.6	1.9	1.7	33.5	24.4	-0.2
(i) लाभांश और लाभ	171	308	325	376	391	0.9	1.1	1.0	80.5	21.8	4.1
(ii) ब्याज प्राप्ति	38	40	48	40	42	0.1	0.1	0.1	5.7	-0.7	4.0
8. राजस्व प्राप्ति (6+7)	2,729	3,037	3,420	3,342	3,533	9.2	9.4	9.0	11.3	10.1	5.7
9. गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति	60	42	76	64	118	0.1	0.2	0.3	-30.0	53.1	84.9
(i) विविध पूंजी प्राप्ति	33	17	47	34	80	0.1	0.1	0.2	-48.1	96.7	136.4
(ii) ऋणों की वसूली	27	25	29	30	38	0.1	0.1	0.1	-7.6	22.6	27.2
10. कुल प्राप्ति (उधार सहित) (8+9)	2,789	3,078	3,496	3,406	3,652	9.3	9.5	9.3	10.4	10.7	7.2
11. राजस्व व्यय (आरई)	3,494	3,601	3,944	3,869	4,125	10.9	10.8	10.5	3.1	7.4	6.6
(i) ब्याज भुगतान (आईपी)	1,064	1,116	1,276	1,274	1,404	3.4	3.6	3.6	4.9	14.2	10.2
(ii) कुल सब्सिडी (टीएस)	435	423	426	470	455	1.3	1.3	1.2	-2.8	11.1	-3.1
जिसका कि:											
खाना	212	200	203	228	228	0.6	0.6	0.6	-5.6	14.2	-0.2
उर्वरक	188	171	168	186	171	0.5	0.5	0.4	-9.4	9.2	-8.4
पेट्रोलियम	12	14	12	15	12	0.04	0.04	0.03	18.3	4.4	-20.1
(iii) आरई-आईपी-टीएस	1,995	2,063	2,242	2,125	2,267	6.2	6.0	5.8	3.4	3.0	6.7
12. पूंजीगत व्यय (i + ii)	949	1,052	1,121	1,096	1,222	3.2	3.1	3.1	10.8	4.2	11.5
(i) पूंजीगत परिव्यय	788	855	895	887	943	2.6	2.5	2.4	8.5	3.8	6.3
(ii) ऋण और अग्रिम	161	197	226	208	279	0.6	0.6	0.7	22.1	5.9	33.8
13. कुल व्यय (11+12)	4,443	4,653	5,065	4,965	5,347	14.1	13.9	13.6	4.7	6.7	7.7
14. राजकोषीय घाटा (13-10)	1,655	1,574	1,569	1,558	1,696	4.8	4.4	4.3	-4.8	-1.0	8.8

स्रोत: यूनिशन बजट दस्तावेज़ ।

अनुलग्नक II: केंद्र से राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को संसाधन हस्तांतरण

वस्तु	₹ हजार करोड़			सकल स्थानान्तरण का प्रतिशत			विकास दर		
	2024-25	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)	2024-25	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)	2024-25	2025-26 (आरई)	2026-27 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण	1286.9	1393.0	1526.3	57.8	59.6	58.2	13.9	8.2	9.6
II. वित्त आयोग अनुदान	120.9	153.0	129.4	5.4	6.5	4.9	-18.6	26.6	-15.4
जिसका कि:									
1. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - शहरी निकाय	19.3	26.0	45.3	0.9	1.1	1.7	-9.2	35.1	74.0
2. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - ग्रामीण निकाय	41.3	54.3	55.9	1.9	2.3	2.1	-12.7	31.6	2.9
3. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	10.6	25.2	-	0.5	1.1	-	126.0	137.4	-
4. एसडीआरएफ के लिए अनुदान सहायता	20.3	24.3	22.6	0.9	1.0	0.9	4.3	19.7	-6.9
5. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए अनुदान सहायता	5.0	9.3	5.6	0.2	0.4	0.2	17.2	85.8	-39.1
6. हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान	24.5	13.7	-	1.1	0.6	-	-52.6	-44.0	-
III. ट्रांसफर की कुछ जरूरी चीजें	202.7	230.1	279.1	9.1	9.9	10.6	26.5	13.6	21.3
जिसका कि:									
1. बाहरी सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट-लोन	34.4	47.2	47.8	1.5	2.0	1.8	9.9	37.1	1.2
2. पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	149.5	150.0	200.0	6.7	6.4	7.6	36.4	0.3	33.3
3. मांग के अंतर्गत विशेष सहायता - राज्यों को अंतरण	3.4	10.0	15.0	0.2	0.4	0.6	-71.4	198.5	50.0
IV. राज्यों को कुल हस्तांतरण [I+II+III के अलावा]	555.1	498.2	609.0	24.9	21.3	23.2	-2.8	-10.3	22.3
1. केंद्र प्रायोजित योजनाएं (राजस्व)	382.3	399.9	520.3	17.2	17.1	19.9	-10.1	4.6	30.1
2. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ	19.2	67.9	77.4	0.9	2.9	3.0	27.0	254.2	14.0
3. व्यय की अन्य श्रेणियाँ	153.6	30.4	11.2	6.9	1.3	0.4	17.3	-80.2	-63.2
4. पूंजी हस्तांतरण	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	5000.0
V. दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर में स्थानांतरण	60.0	61.9	77.0	2.7	2.7	2.9	8.7	3.2	24.4
VI. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सकल हस्तांतरण (I+II+III+IV+V)	2225.5	2336.1	2620.8	100.0	100.0	100.0	7.8	5.0	12.2
VII. ऋण और अग्रिम की कम वसूली	24.6	50.3	50.3	1.1	2.2	1.9	100.9	104.6	0.0
VIII. नेट ट्रांसफर (VI-VII)	2201.0	2285.9	2570.5	98.9	97.8	98.1	7.2	3.9	12.5
IX. सकल हस्तांतरण / जीडीपी (प्रतिशत)	6.7	6.5	6.7	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
X. नेट ट्रांसफर / जीडीपी (प्रतिशत)	6.7	6.4	6.5	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए

स्रोत: यूनिशन बजट दस्तावेज़ ।

अनुलग्नक III: राज्यों से संबंधित सोलहवें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें

डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में सोलहवें वित्त आयोग (एफसी-XVI) ने 17 नवंबर, 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में 2026-27 से 2030-31 तक की पुरस्कार अवधि शामिल है और इसे 1 फरवरी, 2026 को संसद के समक्ष रखा गया था। पंद्रहवें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

कर हस्तांतरण

- ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के तहत विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।
- क्षैतिज अंतरण के तहत, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी दूरी साझाकरण सूत्र में सबसे अधिक महत्व रखती है। इस फॉर्मूले को मध्यम रूप से रीकैलिब्रेट किया गया है, जिसमें जनसंख्या को अधिक महत्व दिया गया है और क्षेत्र और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के लिए भार में मामूली कमी आई है। वन आवरण मानदंड को बरकरार रखा गया है, जबकि कर प्रयास मानदंड को हटा दिया गया है।
- सकल घरेलू उत्पाद में राज्यों का योगदान 10 प्रतिशत भार के साथ एक नया मानदंड पेश किया गया है।

सहायता अनुदान

- राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व घाटा अनुदान को बंद कर दिया गया है, जो पिछली प्रथा से एक महत्वपूर्ण अंतर है।
- किसी भी क्षेत्र विशिष्ट या राज्य विशिष्ट अनुदान की सिफारिश नहीं की गई है, जो पंद्रहवें वित्त आयोग में अपनाए गए दृष्टिकोण से स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है।
- शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के तहत नए घटक पेश किए गए हैं, जिनमें विशेष अवसंरचना घटक और शहरीकरण प्रीमियम शामिल हैं।
- आपदा प्रबंधन अनुदान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के साथ-साथ राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष को अधिक महत्व देने के साथ-साथ आपदा-पूर्व शमन और लचीलापन निर्माण पर अधिक जोर देता है।

मैक्रो और राजकोषीय स्थिरता का मार्ग

- आयोग ने राजकोषीय विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए राज्य के सकल राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक सीमित करने की सिफारिश की और 2030-31 तक केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5 प्रतिशत तक कम करने का अनुमान लगाया।
- 2030-31 तक राज्यों का ऋण मामूली रूप से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 27.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता सहित, समेकित राज्य सरकार का ऋण 2030-31 तक बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 29.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। जबकि कुल ऋण प्रबंधनीय बना हुआ है, अंतर-राज्यीय असमानताएं सख्त राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
- राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे गैर-बजट उधार को समाप्त करें और मानकीकृत बजट रिपोर्टिंग और सीएजी खातों के माध्यम से पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करें।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों को समेकन पथ के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए, उल्लंघनों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए, और घाटे और ऋण सीमा के भीतर ऑफ-बजट उधार शामिल किया जाना चाहिए।

संरचनात्मक परिवर्तन

- राज्यों को डिस्कॉम निजीकरण को आगे बढ़ाना चाहिए, संचित ऋण को एक विशेष प्रयोजन वाहन में स्थानांतरित करना चाहिए। इस ऋण के पूर्व भुगतान या पुनर्भुगतान को विशेष पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना से जोड़कर संघ प्रोत्साहन के लिए पात्र बनाया जाएगा।
- राज्यों को केवल अच्छी तरह से लक्षित योजनाओं को बनाए रखकर, सनसेट या एग्जिट क्लॉज को लागू करके, ऑफ-बजट वित्तपोषण को बंद करके और मानकीकृत सीएजी रिपोर्टिंग के माध्यम से व्यापक प्रकटीकरण सुनिश्चित करके सब्सिडी की समीक्षा और युक्तिसंगत बनाना चाहिए।
- केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहिए, राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए निष्क्रिय संस्थाओं को बंद करना चाहिए और वैकल्पिक उत्पादक उपयोगों के लिए अपनी भूमि और भवनों को फिर से तैनात करना चाहिए।